

साप्ताहिक

शांति मिशन

नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 31

01 - 07 अगस्त 2021

पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

महामारी में महंगाई का संकट

पृष्ठ - 6

परमाणु हथियारों का बढ़ता ज़ख़ीरा

पृष्ठ - 7

अमेरिका और नाटो संघर्ष सेना की अफगानिस्तान से वापसी क्या अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सकेगी?

अमेरिका और नाटो देशों की सशस्त्र सेना के अफगानिस्तान से निकलना जारी है जबकि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है, ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सकेगी?

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान को अधर में छोड़ दिया है। उसके और नाटो देशों की सैनिकों की वापसी जारी है। इस बीच अफगानिस्तान में घट रही घटनाएं अफगानी जनता के साथ साथ एशियाई देशों को भी परेशान कर रही हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने हमले तेज़ कर दिए हैं। कई इलाकों को अफगान सेना से छीन लिया है इससे तालिबान की रणनीति अब स्पष्ट हो गई है। तालिबान ने काफी चालाकी से दोहा शांति वार्ता को धीमा रखा था वह अमेरिकी सैनिकों की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। दोहा में बातचीत अभी रुकी हुई है पर तालिबान की इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तान खुश है। हालांकि चीन और ईरान परेशान है इसीलिए अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में ईरान और चीन सक्रिय हो गए हैं क्योंकि दोनों देशों को अलग अलग कारणों से पाकिस्तान नियंत्रित तालिबान पर भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात 2001 से अलग हैं।

अफगानिस्तान में भविष्य की समस्या सिर्फ गृह युद्ध तक ही सीमित नहीं है। अगर संघर्ष बढ़ा तो इस देश की माली हालत और बिगड़ती चली जाएगी। अफगान वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि तालिबान के हमलों में तेज़ी की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह को भारी नुकसान पहुंचा है। सीमा शुल्क की वसूली में कमी आई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में दूसरे दर्जे वाले कुछ सीमा शुल्क केंद्रों पर अफगान सरकार के नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया है। इस समय सीमा शुल्क संग्रहण पचास करोड़ अफगानी के बजाय पन्द्रह करोड़ अफगानी प्रतिदिन रह गया है, यानि इसमें दो तिहाई रोज़ाना की गिरावट आई है। हालांकि एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि तालिबान के हमले को सिर्फ बहाना बनाया गया है। दरअसल सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। अधिकारी तालिबान का बहाना बना खुद पैदा बटोर रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि अफगानिस्तान सरकार की आय कैसे बढ़ेगी, देश को चलाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से?

20 वर्ष पहले अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी नाटो देशों का जो जोश देखते बनते था, वह हताशा में बदल चुका है अफगानिस्तान में दो दशक से फंसे अमेरिका की स्थिति हर तरह से कमज़ोर हो गई है दो दशकों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान के अधियान पर अब तक के सैन्य खर्च ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका यह अच्छी तरह से समझ चुका है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर भी उसका वही हाल हो रहा है जो वियतनाम और ईराक में हुआ और

रही है। तालिबान का दावा है कि उसने देश के एक तिहाई जिलों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है इसलिए अब आने वाले दिनों में तालिबान और अफगानि सेना के बीच और तेज़ होगी। इस खतरे से कोई इंकार नहीं करेगा कि तालिबान के आतंकाती हमले बढ़े और इस हिस्से में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। इन हालात में अफगानिस्तान में लंबा गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। अगर इसमें पड़ोसी मुल्कों ने हस्तक्षेप किया तो तालिबान की भी मुश्किल ज़्यादा बढ़ेगी। कई जगहों पर स्थानीय अफगान आबादी

चली जाएगी। अफगान वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि तालिबान के हमलों में तेज़ी की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह को भारी नुकसान पहुंचा है। सीमा शुल्क की वसूली में कमी आई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में दूसरे दर्जे वाले कुछ सीमा शुल्क केंद्रों पर अफगान सरकार के नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया है। इस समय सीमा शुल्क संग्रहण पचास करोड़ अफगानी के बजाय पन्द्रह करोड़ अफगानी प्रतिदिन रह गया है, यानि इसमें दो तिहाई रोज़ाना की गिरावट आई है। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ़ संघर्ष के नाम पर पश्चिम देशों ने अफगानिस्तान को खासी आर्थिक मदद दी। अफगानिस्तान में विकास कार्य तेज़ करने की कोशिशें भी की गईं। अफगानिस्तान सरकार को सैन्य सहयोग राशि भी दी गई। लेकिन इन सबका कोई लाभ दिखा नहीं। आज यह उसकी प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं। अमेरिकी नीति ऐसे देशों को फंसाए रखने की ही रही है। तभी अमेरिकी हित पूरे होते हैं। पिछले दो दशक से काबुल पर राज करने वाले अफगान नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ़ संघर्ष के नाम पर पश्चिम देशों ने अफगानिस्तान को खासी आर्थिक मदद दी। अफगानिस्तान में विकास कार्य तेज़ करने की कोशिशें भी की गईं। अफगानिस्तान सरकार को सैन्य सहयोग राशि भी दी गई। लेकिन इन सबका कोई लाभ दिखा नहीं। आज काबुल में ईरान सारी जातियों की सम्मिलित सरकार चाहता है। ईरान कई कारणों से अफगानिस्तान को लेकर गंभीर है। ईरान की लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इस सीमा पर वे राज्य हैं जहां तालिबान मजबूत है। ये अफगानी राज्य ईरान के लिए सामरिक और आर्थिक महत्व वाले हैं क्योंकि इन राज्यों से ही पाकिस्तान के क्वेटा से तुर्कमेनिस्तान तक जाने वाला आर्थिक गलियारा गुज़रता है। ईरान को पता है कि अगर काबुल पर पाकिस्तान का एकछत्र राज हो गया तो इस इलाके

अफ़ग़ानिस्तान में क्या करे भारत

भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान में इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है। भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान में आशंकाएं उस समय से भी बदतर प्रतीत होती हैं, जब 1992 में वहाँ इसकी समर्थक सरकार गिर गई थीं। तब तक सेवियत संघर, जिसके साथ भारत का गठबंधन था, विघटित हो गया था। भारत एक बार फिर वहाँ अलग-थलग है, क्योंकि उस क्षेत्र में इसके करीबी माने जाने वाले अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने अशरफ़ ग़नी सरकार को तालिबान के गंभीर ख़तरे के बीच छोड़ दिया है, और तालिबान का भारत से कभी बेहतर रिश्ता नहीं रहा।

अगर भारत तालिबान के साथ देर से और संकोच के साथ बात कर भी रहा है, तो लगता है कि शायद वह कारगर नहीं हो रही, क्योंकि तालिबान का शीर्ष नेतृत्व, जिसका वास्तव में कूटनीतिक महत्व है, अपना वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान पर पूरी तरह कब्ज़ा करने में व्यस्त है, ताकि देश के भीतर या बाहर से उसे चुनौती न दी जा सके।

तालिबान के नियंत्रण में अफ़ग़ानिस्तान का कितना बड़ा इलाका है, यह अब मायने नहीं रखता। उन्होंने

यह दिल्ली है

चुनौती दे रहा है, हालांकि अमेरिका भी उसे चुनौती दे रहा है।

ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका अब भी इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी शक्तियों को एकजुट करने में उम्मीद करता है। अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से बाहर उच्च तकनीक वाले 'हाइब्रिड युद्ध' की योजना बना रहा है, जैसा कि सीरिया में किया गया था। इस

दो दशकों तक तालिबान को सफलतापूर्वक पनाह और समर्थन देने, अफ़ग़ानिस्तान में उनके मौजूदा सैन्य अभियान को सुविध अजनक बनाने तथा चीन का समर्थन सुनिश्चित करने का यह पाकिस्तानी रुख़ भारत के लिए उतना ही चिंताजनक होना चाहिए, जितना कि अमेरिका और पश्चिमी ताक़तों के लिए। यहाँ की खनिज संपदा में चीन की पहले से गहरी दिलचस्पी है।

योजना के तहत तुर्की और कुछ मध्य एशियाई देशों में सैन्य अडडा बनाने की परिकल्पना की गई है। उज्जेकिस्तान और ताजिकिस्तान से संपर्क किया जा रहा है। पर अपनी धरती पर रूसी हथियारों की मौजूदगी और बगल में चीन के होते हुए ऐसा नहीं लगता कि वे अमेरिकियों को अफ़ग़ानिस्तान में ले आया था। आज चीन एक विश्व शक्ति है, जो अमेरिका को

तालिबान ने अमेरिका की मदद के खिलाफ़ सबको चेताया हैं हैरानी की बात नहीं कि 9/11 के बाद के सालों में आतंकवाद के खिलाफ़ अमेरिकी जंग का पूर्व बहादुर सेनानी पाकिस्तानी अमेरिकियों को हवाई क्षेत्र और समर्थन देने से इंकार करने वाला पहला देश बन गया है। चीन के समर्थन पर इमरान ख़ान सुरक्षित खेल खले रहे हैं।

दो दशकों तक तालिबान को सफलतापूर्वक पनाह और समर्थन देने, अफ़ग़ानिस्तान में उनके मौजूदा सैन्य अभियान को सुविध अजनक बनाने तथा चीन का समर्थन सुनिश्चित करने का यह पाकिस्तानी रुख़ भारत के लिए उतना ही चिंताजनक होना चाहिए, जितना कि अमेरिका और पश्चिमी ताक़तों के लिए। अफ़ग़ानिस्तान की खनिज संपदा में चीन की पहले से गहरी दिलचस्पी है। अफ़ग़ानिस्तान में चीन-पाक गठबंधन बढ़ा आकार लेने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफ़ग़ानिस्तान तक बढ़ा रहा है। अगर अमेरिकी 'हाइब्रिड' युद्ध अशरफ़ ग़नी को काबुल में राष्ट्रपति पद पर बनाए रखने में सफल नहीं होता, तो ऐसा जल्दी ही हो सकता है।

भारत के लिए अगर कुछ सांत्वना की बात है, तो यह कि पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत जटिल है। अफ़ग़ानिस्तान में खुली छूट मिलने और काबुल में एक मित्र सरकार होने की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। सत्ता पर काबिज़ हो जाने पर तालिबान उनके मित्र बने रहेंगे और वे दुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करेंगे, यह देखा जाना बाकी है। फिलहाल पाकिस्तान शरणार्थियों की आमद की उम्मीद कर सकता है, जो पहले से ही अनुमति 28 लाख है। इसके अलावा नशीले पदार्थ भी आएंगे। इसके साथ चरमपंथियों और सांप्रदायिक समूहों की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अफ़ग़ान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान में वैचारिक समानता है। चीन भी इससे डरता है, इसलिए वह शिनजियांग में उड़गरों को कुचलने की कोशिश कर रहा है।

पिछले दो दशकों में भारत ने अफ़ग़ानों से जो सद्भावना अर्जित की, वह तालिबान के सत्ता में आते ही समाप्त हो जाएगी। अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भारत ने तीन अरब डॉलर से अधिक का जो निवेश किया, वह फिलहाल

बाकी पेज 11 पर

यह दिल्ली है

टीसी के बिना भी होगा सरकारी स्कूलों में दाखिला

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अब बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने का फैसला लिया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे निजी स्कूल बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं। वे उनसे एक वर्ष की फीस मांग रहे हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अधिभावक चाह कर भी अपने बच्चों को निजी स्कूल से

लेना चाहता है तो टीसी न होने की वजह से उसे दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे निजी स्कूल बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं। वे उनसे एक वर्ष की फीस मांग रहे हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अधिभावक चाह कर भी अपने बच्चों को निजी स्कूल से

निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत सारे अधिभावकों से ऐसी शिकायत मिलने के बाद ही इस बाबत शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया गया है।

श्री सिसौदिया ने कहा कि यदि स्कूल टीसी देने से मना कर रहा है तो बाकी दस्तावेज़ के आधार पर भी बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले

सकते हैं। उन्होंने अधिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे चिंता न करें। बच्चों के पिछले स्कूल से टीसी लाने का काम शिक्षा निदेशालय स्वयं करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए 28,000 से अधिक आवेदन मिले

हैं। छठी से 12वीं कक्षा के लिए 90,000 आवेदन आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छठी से नवीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्र 23 जुलाई से छह अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11वीं के लिए आवेदन दसवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद किए जा सकेंगे।

मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी : सिसौदिया

ओलंपिक शुरू हो चुका है, और पहले ही दिन भारत की मीरा कुमार चानू ने रजत पदक जीतकर उम्मीदें बढ़ा दी है। इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पिछले दिनों उनसे वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर दिल्ली और देश का नाम रोशन करेंगे।

टोक्यो ओलंपिक में दिल्ली के चार खिलाड़ी मनिक बत्रा, दीपक कुमार, अमोज जैकब और सार्थक भांबरी टेबिल टेनिस, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी दिल्ली सरकार के मिशन एक्सीलेंस स्कीम का हिस्सा रह चुके हैं। उपमुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे ओलंपिक में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें और तानावमुक्त होकर खेलें। दिल्ली और देश के सभी लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। संवाद के दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के मिशन एक्सीलेंस से उन्हें प्रशिक्षण के दौरान काफी सहायता मिली है। वहीं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की उपकूलपति कर्णमल्लेश्वरी ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें।

तपती धरदानी बढ़ती दृश्वारियाँ

मौसम का चरित्र बदलने से तनाव के सामने अनगिनत समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। मगर जिनके चलते समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन कारणों को जानते हुए भी उन्हें खत्म करना कठिन हो गया है। गैरतलब है कि उन कारणों में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बढ़ते जाना और प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना दोहन प्रमुख है।

भारत मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार 1901 से लेकर 2020 के दरम्यान भारत के औसत तापमान में 0.17 डिग्री की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 2016 भारत का अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है अब तक के पन्द्रह सर्वाधिक गर्म सालों में से बाहर वर्ष 2006 के बाद दर्ज किए गए हैं। मौसम के बदलाव ने आम आदमी और वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। खेती, किसानी, बागवानी और औषधियों से जुड़े सभी क्षेत्रों पर ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरनाक असर पिछले बीस सालों से देखा जा रहा है, उससे कई तरह की समस्याएं और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गैरतलब है कि पिछले बीस सालों में कृषि उत्पादों में 15 प्रतिशत तक कमी आई है। वैश्विक पैदावार में चार प्रतिशत की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में धान के उत्पादन वाले लगभग चालीस प्रतिशत क्षेत्र के खेती लायक न रह जाने की आशंका जताई गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धान, गेहूं, जौ और आलू जैसी फसलों में पौष्टिक गुणों में छह प्रतिशत तक की कमी आई है। गैरतलब है कि अगर पौष्टिक गुणों की कमी आगे भी बनी रही तो खाद्यान्न मानव सभ्यता के रक्षक नहीं बल्कि समस्या बने रहेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के असर से बारिश का स्वरूप असंगत हुआ है। इससे समय से पहले, तो कहीं समय बीत जाने पर बहुत अधिक बरसात होने की वजह से फसल चक्र पर जबरदस्त असर देखा जा रहा है। गैरतलब है कि आज से चालीस या पचास वर्ष पहले के मौसम और आज के मौसम में आए बदलावों को जो जानते हैं उनका मानना है कि पर्यावरण प्रदूषण ने हर क्षेत्र में व्यापक असर डाला है, जिससे ऋतु चक्र और दूसरे तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त असर हुआ है।

मौसम का चरित्र बदलने से तनाव के सामने अनगिनत समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। मगर जिनके चलते समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन कारणों को जानते हुए भी उन्हें खत्म करना कठिन हो गया है। गैरतलब है कि उन कारणों में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बढ़ते जाना और प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना दोहन प्रमुख है।

रोज़गार

कैरियर चुनने में जल्दबाज़ी न करें

आज हम सुन रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है, और लोग इस विपत्ति के अपने लिए कूठां मान लेते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग अपने काम में सैलरी पसंद करते हैं, मगर जॉब से बोर हो जाते हैं। जितने मन से आपने कैरियर चुना था, अब आपको लगता है कि यह तो वह काम नहीं है, जो आप करना चाह रहे थे। दरअसल, कैरियर में अगर संतुष्टि न हो, न तो भविष्य सुरक्षित होता है और न ही मन को शारीरिक गुणों में जॉब करके अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो तो आपको फिर से गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है।

समस्या को पहचानें

कई बार एक ही काम करते-करते अक्सर युवा बोर होने लगते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि यह वह काम नहीं है, जिससे उसे प्यार था फिर वह दूसरा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको दूसरे कैरियर में जाना चाहिए। क्या इनमें से कोई समस्या तो नहीं है, जिस कारण आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। बॉस अकड़ू है, सैलरी कम है, या काम की अधिकता है।

कैरियर ग्रलत चुना या

सोच बदल गई?

कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपने

मिली दर्ज की गई। बरसात का लगातार कम होना इस बात का संकेत है कि अगर इसी तरह वर्षा कम होने का क्रम बना रहा, तो आने वाले कुछ दशकों में बरसात की जगह अकाल ले सकता है। इससे विश्व स्तर पर भुखमरी, तरह तरह की बीमारियां, जंगलों और हरियाली का विनाश, भूजल स्तर के नीचे जाने, पीने के पानी की किल्लत सहित अनगिनत समस्याओं और संकटों से विश्व को सामना करना पड़ सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग के असर से मध्य भारत में पिछले पैसंठ सालों में बारिश में गिरावट आई है। ऋतुचक्र में बदलाव की वजह से असमय बारिश,

सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी परिस्थितियां निरंतर निर्मित हो रही हैं। इससे विस्थापन एक स्थायी समस्या का रूप ले सकता है। अनुमान के मुताबिक जल संकट, सूखे, कृषि संकट और समुद्री जल स्तर में बढ़ोत्तरी की वजह से 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में तीन से चौदह करोड़ आबादी पर आंतरिक विस्थापन का खतरा मंडरा सकता है। अगला युद्ध जल के कारण मानने वालों की आशंका सही सवित होती दिखाई पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने माना है कि आने वाले सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण भूमिगत जल के स्तर में लगभग तीन चौथाई

की कमी के कारण ढाई अरब और लोग जल संकट से जूझ रहे होंगे। ऐसी स्थिति में विश्व स्तर पर पानी के बाबत 'जल युद्ध' छिड़ सकता है। गैरतलब है कि पचास प्रतिशत विश्व की आबादी पानी के संकट से आज भी जूझ रही है।

बहुत कम लोग जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से विश्व के गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। आने वाले समय में भोजन, पानी और दवाओं के कमी की समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। अनुमान है कि आने वाले सालों में एक करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषण और बौनेपन का शिकार होंगे, जिससे गरीब परिवारों के सामने तरह-तरह की नई समस्याएं पैदा होंगी। बढ़ते धरती के तापमान की वजह से जिस तरह से गर्मी, ठंडक और बेमौसम बरसात की समस्याएं बढ़ रही हैं, उससे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, पीला बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए सरकारों को अतिरिक्त संसाधन और धन व्यय करने की विवशता होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का असर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनकी डायरिया से होने वाली मौतों का दायरा और आंकड़े बेतहाशा बढ़ेंगे।

ग्रीन हाऊस गैसों से बढ़ते प्रदूषण के चलते कई दूसरी समस्याएं भी पैदा होने लगी हैं। इससे दुनिया में एक तरह से मौसमी आतंकी की छाया देखने को मिलने लगी है। अमेरिका जैसे देश में बर्फीले तूफान ने पिछले सालों में जो कहर ढाया, उसे वहां के लोग शायद कभी न भूला पाएं। ऐसे ही भारत में पिछले सालों में उत्तराखण्ड, बिहार, तमिलनाडू और हालिया महाराष्ट्र के कई ज़िलों भारी बारिश से तबाही ने लोगों को हल्कान कर दिया है।

ग्लोबल वार्मिंग का असर महानगरों, शहरों में रहने वाले लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। लोगों के अंदर सहनशीलता, सुख सुविधाओं के कारण बहुत कम होती जा रही है। सम्पन्न परिवारों में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सुख सुविधाओं में जीने के आदि हो गए हैं।

हिंसा के बीच पीओके में
जीती इमरान की पार्टी

इस्लामाबाद : प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव में भारी हिंसा व धांधली के आरोपों के बीच पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उसने 45 में से 25 सीटें जीतीं जबकि पीपीपी ने आठ और पीएमएल-एन ने सिर्फ़ छह सीटें जीतीं।

ट्यूनिशिया : राष्ट्रपति ने हिस्कं प्रदर्शनों के बीच पीएम को किया बख्खास्त

ट्यूनिश : उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिशिया में राष्ट्रपति कैसे सैयद ने देश में जारी हिस्कं प्रदर्शनों के बीच संसद भंग कर पीएम हिचम मेचिचि को बख्खास्त कर दिया है। विपक्ष ने इसे तख्लापलट बताया है जबकि राष्ट्रपति ने कहा कि उनका यह कदम सांविधानिक दायरे में है। इस फैसले की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए जश्न मनाया। ट्यूनिशिया के लोग कोरोना से निपटने में सरकार की नाकामी से गुस्से में प्रदर्शन कर रहे थे। हिस्कं प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने देश में शांति लाने के इरादे से यह कदम उठाया है।

22 हजार परिवार भागकर काबुल आए

काबुल : तालिबान के भीषण हमलों से भयभीत हजारों नागरिक काबुल चले आए हैं। तालिबान के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए अफगान सरकार ने कई क्षेत्रों में रात का कफ्फूल लगा दिया है। यहां अभी भी सरकारी सेना का नियंत्रण है। गजनी से भागकर काबुल आए एक पिता ने बताया कि उसके दो बेटों को तालिबान ने मार डाला। ये लोग न तो सरकारी कर्मचारी थे और न ही सुरक्षाकर्मी। तकरीबन 22 हजार अफगान परिवार भागकर काबुल में आ चुके हैं।

के/2 पर चढ़ाई में स्कॉटलैंड के पर्वतारोही की मौत

अर्थशास्त्र की भाषा में, विशेषतौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को अच्छा माना जाता है, बशर्ते यह मांग आधारित हो। मांग बढ़ने का अर्थ होता है कि लोगों के पास कमाई है और वे अधिक उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपभोग घट चुका हो, महंगाई फिर भी बढ़ रही हो और यह स्थिति अधिक समय तक टिकी रह जाए तो एक आत्मघाती परिस्थिति पैदा होने लगती है। देश कमोबेश इसी दौर से गुज़र रहा है। मांग बुरी तरह घटी हुई है प्रति व्यक्ति निजी उपयोग 2020-2021 में घटकर 55,783 रुपय हो गया, जो 2019-20 में 62,056 रुपए था। पिछले चार सालों से निजी उपभोग में गिरावट का रुख़ है। कोरोना काल में इसमें ज्यादा गिरावट आई। वित्त वर्ष 2021-22 में भी उपभोग में गिरावट रहने का अनुमान है।

अमेरिकी विचार समूह-पेव रिसर्च सेंटर के अनुमान के अनुसार भारत में दो डॉलर या डेढ़ सौ रुपए से

महंगाई में महंगाई का संकट

आमदनी अठनी खर्चा रुपैया वाले मुहावरा अब गुज़रे ज़माने की बात है। महंगाई और कमाई की मौजूदा परिस्थिति नया मुहावरा गढ़ने की ओर बढ़ रही है, जहां आमदनी की अठनी भी ग़ायब हो सकती है। आम आदमी की तस्वीर नए मुहावरे में कैसी होगी, कह पाना कठिन है। फिलहाल मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है और आमदनी न होने पर भी ख़र्च मजबूरी बन गया है। अर्थव्यवस्था का यह चरित्र एक विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है। खुदरा महंगाई दर जून में लगातार दूसरे माह छह प्रतिशत से ऊपर रही है। इसके नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि थोक महंगाई दर का रुख़ तेज़ी से ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है।

मई में यह रिकॉर्ड 12.94 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अप्रैल में 10.49 प्रतिशत थी। वर्ष 2010 के बाद पहली बार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर दो अंकों में दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर की यह ऊंचाई आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर को ऊपर ले जाएगी। यानि आगे का समय आम आदमी के लिए, विशेष तौर पर से ग़रीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके तेईस करोड़ लोगों के लिए कठिन रहने वाला है।

अर्थशास्त्र की भाषा में, विशेषतौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को अच्छा माना जाता है, बशर्ते यह मांग आधारित हो। मांग बढ़ने का अर्थ होता है कि लोगों के पास कमाई है और वे अधिक उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपभोग घट चुका हो, महंगाई फिर भी बढ़ रही हो और यह स्थिति अधिक समय तक टिकी रह जाए तो एक आत्मघाती परिस्थिति पैदा होने लगती है। देश कमोबेश इसी दौर से गुज़र रहा है। मांग बुरी तरह घटी हुई है प्रति व्यक्ति निजी उपयोग 2020-2021 में घटकर 55,783 रुपय हो गया, जो 2019-20 में 62,056 रुपए था। पिछले चार सालों से निजी उपभोग में गिरावट का रुख़ है। कोरोना काल में इसमें ज्यादा गिरावट आई। वित्त वर्ष 2021-22 में भी उपभोग में गिरावट रहने का अनुमान है।

अमेरिकी विचार समूह-पेव रिसर्च सेंटर के अनुमान के अनुसार भारत में दो डॉलर या डेढ़ सौ रुपए से

कम कमाने वाले ग़रीबी की संख्या डॉलर प्रति बैरल थी। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सौ रुपए प्रति लीटर के पार से भी ऊपर पहुंच गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ती है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। परिणामस्वरूप सामान महंगे हो जाते हैं। पिछले सात माह में यह पहला मौक़ा है, जब खुदरा महंगाई दर लगातार दो माह से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। दुखद पक्ष यह है कि जून में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर और बढ़ गई और यह 5.15 प्रतिशत दर्ज की गई। मई में यह 5.01 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल में मात्र 1.96 प्रतिशत। खाने पीने का सामान महंगा होने से आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है।

सरकार ने मार्च 2026 तक महंगाई दर को दो फीसद से छह फीसद के बीच बनाए रखने के लिए आरबीआई को निर्देश दे रखा है। आरबीआई ने महंगाई अपने आप में महामारी न बन जाए, इससे पहले इसे रोकने के कदम उठाने ही होंगे। फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई पर नियंत्रण के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। मौद्रिक और राजकोषीय। मौद्रिक उपाय के तहत आरबीआई बाजार से तरलता खींचकर मांग घटाने की कोशिश करता है। राजकोषीय उपाय में भी सरकार कर बढ़ा कर मांग घटाने की कोशिश करती है लेकिन मौजूदा परिस्थिति मांग घटाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि बाजार से मांग पहले से ही लुढ़की हुई है। हां, सरकार उन अरबपतियों पर विशेष कर लगा सकती है, जिनकी संपत्ति कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक पैंतीस फीसद बढ़ गई है। इसके अलावा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर शुल्क घटाए जा सकते हैं।

महंगाई कम करने के लिए तेल की कीमतें हर हाल में घटानी होंगी। सरकार उत्पाद शुल्क के उस हिस्से को आसानी से वापस ले सकती है, जिसे कोरोना काल के दौरान बढ़ाया गया था। मांग न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आई भारी गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को न मिल जाए, इसके लिए सरकार ने मार्च से मई, 2020 के बीच दो बार में पेट्रोल पर तेह रुपए और डीजल पर सोलह रुपये विशेष उत्पाद शुल्क लगा दिया था। इस विशेष उत्पाद शुल्क को बाद में वापस लेने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तेल की कीमत घटने से महंगाई में तत्काल राहत मिलेगी। मौजूदा परिस्थिति में सरकार को कर्ज़ लेकर अधिक ख़र्च करने की भी ज़रूरत है। लोगों की जेब में पैसे जाएंगे तो वे महंगाई से मुक़ाबला भी कर लेंगे। बेशक इससे राजकोषीय घटाए बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति से निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है, चार किलो मुफ्त अनाज तो बिल्कुल भी नहीं।

पेगासस : इस्राईल और
फ्रांस एनएसओ में
करेंगे चर्चा

येरुशलम : दुनियाभर में पेगासस से जासूसी को लेकर मच रहे बवाल के बीच इस्राईल और फ्रांस पेरिस में स्पाइवरेयर कंपनी एनएसओ पर चर्चा कर सकते हैं। इस जानकारी के अनुसार इस्राईली रक्षा मंत्री बेनी गैट्ज अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लतरेंस पानी के साथ बैठक के लिए दौरे पर जाएंगे। दोनों की मुलाकात के दौरान लेबनान संकट और विश्व शक्तियों के अलावा ईरान के साथ परमाणु वार्ता पर भी बातचीत होगी।

असहनीय निगरानी के बीच चीनी कवि ली हुइजी ने की खुदकुशी

गुआंगदोंग : राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में असहनीय निगरानी के बीच चीन के कवि और करंट अफेयर्स के स्टंभकार ली हुइजी ने आत्महत्या कर ली है। वे शी जिनपिंग की नीतियों के प्रत्यक्ष आलोचक रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक 62 वर्षीय ली हुइजी ने ग्वांगदोंग के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। हुइजी के दोस्त ली जुवेन ने बताया कि कवि ने एक सुसाइड नोट अँनलाइन पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था कि शी के सत्ता संभालने के बाद से सार्वजनिक अभिव्यक्ति की आजादी की जगह कम होती जा रही है।

भारतवंशी को नस्ली टिप्पणी में जेल

सिंगापुर : भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सिंगापुर में एक सार्वजनिक अस्पताल में नस्ली टिप्पणी करने और स्टाफ पर हमला करने के मामले में पांच सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 52 वर्षीय पेरियानायगम अप्पावू को यहां की एक अदालत ने उत्पीड़न के दो आरोपों और आपराधिक बल प्रयोग के एक आरोप में दोषी ठहराने के बाद यह सजा सुनाई।

इराक में 18 वर्ष बाद खत्म होगा अमेरिकी युद्ध मिशन

वाशिंगटन : राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीकी के साथ बैठक में पुष्टि की है कि अमेरिका 2021 के अंत तक इराक में अपने युद्ध मिशन को खत्म कर देगा। बाइडेन ने कहा, अमेरिकी सेना इराक़ के बलों को आईएस के खिलाफ़ प्रशिक्षण और सहायता देना जारी रखेगी। दोनों देशों ने 18 वर्ष बाद इराक़ में अमेरिकी लड़ाकू मिशन खत्म करने के समझौते पर दस्तख़त कर दिए। अमेरिका व इराक़ ने भी वाशिंगटन में हुई एक रणनीतिक वार्ता के बाद सांझा बयान में कहा कि युद्धक निभाने वाली अमेरिकी सेना 31 दिसंबर तक इराक़ से वापसी कर लेगी।

परमाणु हथियारों का बढ़ता जुखाई

संजय वर्मा

हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बम हमले के बाद से दुनिया में इस प्रश्न पर विचार चलता रहा है कि आखिर परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या है। मसला यह है कि एक ओर इससे पैदा की जाने वाली बिजली को ज़रूरी बताया जाता है, तो दूसरी ओर परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। साफ सुधरी बिजली की बात हो तो परमाणु ऊर्जा की बकालत करने वालों की कमी नहीं है। इस समय दुनिया में करीब दस प्रतिशत बिजली नाभिकीय संयंत्रों (न्यूक्लियर रिएक्टरों) से ही पैदा हो रही है। इस ऊर्जा की बकालत की मूल बजह यह है कि परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का सबसे उम्दा विकल्प माना जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर परमाणु बिजली संयंत्र बनते हैं तो उनसे जुड़ा वह ख़तरा भी हमारे सामने आ जाता है कि कहाँ दुनिया इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने और उनके भंडारों में बढ़ोत्तरी के लिए न करने लगे। इधर, चीन के ऐसे ही बर्ताव ने इस संकट का साफ संकेत किया है।

कुछ समय पहले ही अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के पश्चिम प्रांत गांग्हू के यूमेन शहर के पास रेगिस्तान में सौ से अधिक मिसाइल साइलोज (मिसाइल रखने के ठिकाने) बनाए जा रहे हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल तरल ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलों को रखने के लिए होगा। ऐसी मिसाइलों परमाणु हथियारों से लैस होती है। ये अत्यधिक ऊर्जा की मदद से लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इन साइलोज का महत्व यह है कि इनमें रखी जाने वाली मिसाइलों की न सिर्फ देखभाल और मरम्मत आसानी से हो जाती है। इन ठिकानों के निर्माण को चीन की परमाणु नीति में उल्लेखनीय बदलाव के रूप में दर्ज किया है। एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने में समर्थ ये मिसाइलों अमेरिका तक मार कर सकती हैं। वैसे तो ऐसी मिसाइलों के निर्माण को परमाणु प्रतिरोध (डेटरेंट) का ज़रिया माना जाता है, यानि इनकी मौजूदगी के आधार पर या उनका भय दिखा कर कोई देश दुश्मन देशों से ऐसे हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चीन

के हालिया रुख़ को देख कर इसकी गारंटी नहीं रह गई है कि वह इन परमाणु मिसाइलों का उपयोग सिर्फ प्रतिरोध के लिए करना चाहता है। चीन अब ऐसी प्रतिस्पर्धा बाली नीति अपना रहा है जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर असंतुलन का ख़तरा बढ़ सकता है। न्यूनतम प्रतिरोध की परमाणु नीति से हटते हुए परमाणु हथियारों का ज़ख़्मीरा बढ़ाने की उसकी नीति न्यूक्लियर ट्रायड यानि ज़मीन आसमान और समंदर से परमाणु हथियार दाग़ने की क्षमता विकसित करने पर केन्द्रित हो गई है। यह उसके रुख़ में लगातार बढ़ रही आक्रामकता का स्पष्ट संकेत है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास फिलहाल लगभग दो हज़ार परमाणु हथियार हैं। अब चूंकि चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, ऐसे में बहुत मुप्रकिन है कि उसके परमाणु

चीन ने पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। उसके बाद से उसने पैंतालीस परमाणु परीक्षण किए हैं। हालांकि चीन ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर दस्तख़त किए हैं, फिर भी उसके पास तीन सौ बीस परमाणु हथियार बताए जाते हैं। इनमें से सौ के करीब लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगे हैं। वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करने वाले भारत ने अब तक सीटीबीटी पर परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का अनुमोदन भले नहीं किया है, लेकिन वह अपने परमाणु हथियारों का किसी देश पर पहले इस्तेमाल नहीं करने (नो फस्ट यूज) की नीति पर कायम है। भारत की नीति दुनिया में भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन 1998 में परमाणु परीक्षण करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की मंशा पर किसी को यकीन नहीं है।

हथियारों की संख्या मौजूदा संख्या के मुकाबले दोगुनी हो जाए। उल्लेखनीय है कि हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सौ वर्ष पूरे होने पर दिए गए भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन को डराने का प्रयास करने वाली विदेशी ताकतों का सिर कूचल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। ऐसे बयानों और कर्तव्याईयों से चीन के इदां पर संदेह होता है।

पर प्रश्न है कि परमाणु हथियारों की होड़ पैदा करने में क्या सिर्फ चीन की ही भूमिका रही? इसका एक गंभीर पक्ष यह है कि विकसित देशों से लेकर विकासशील और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में परमाणु हथियारों की भूख बढ़ती जा रही है। अंकलन कहता है कि अमेरिका के पास आज भी तीन हज़ार आठ सौ परमाणु हथियार हैं। इनमें से साढ़े सत्रह सौ हथियार विभिन्न मोर्चों पर

वाले रूस ने अमेरिका से चार साल बाद 1949 में अपना पहला परमाणु हथियार जमा कर लिए। वर्ष 1986 में रूस भी चालीस हज़ार से अधिक परमाणु हथियारों के ज़ख़ीरे पर बैठा था। हालांकि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद रूस-अमेरिका से काफी कम संख्या में परमाणु हथियार हैं। शायद यही वजह है कि वह अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ नए हथियार नियंत्रण समझौते में शामिल नहीं हो रहा है। इस दबाव को खारिज करते हुए चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता रहा है कि चीन को पश्चिमी देशों की राय की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से हथियार बनाने चाहिए।

चूंकि ज़्यादातर देश शक्ति संतुलन साधने के लिए परमाणु हथियारों की ज़रूरत की व्याख्या अपने मन मुताबिक करते रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में इसकी संभावना कम ही है कि इस सिलसिले में कोई प्रभावी रोक लग सकेगी। इसलिए न्यूनतम प्रतिरोध और जवाबी कार्रवाई करने के लिए विश्वसनीय परमाणु क्षमता हासिल करने की इस भूख का अंत कूटनीतिक स्तर पर ही संभव है। संकट यह है कि अगर किसी छोटी सी वजह से भी दुनिया के किसी कोने में एक बार परमाणु अस्त्र चलने लगे, तो शायद अब कोई ज़ंग दुनिया के सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी। □□

